झंडा हटाने को लेकर भिड़े दो संगठन

एसीपी सारनाथ का फटा सिर, एक दरोगा समेत अन्य पुलिसकर्मी हुए घायल

वाराणसी, 17 अप्रैल. वाराणसी के चोलापुर थाना क्षेत्र का नेहिया गांव एक मामूली दिखने वाला झंडा विवाद अचानक इतना बढ़ गया कि दो संगठनों के बीच सीधी भिड़ंत हो गई.

शुक्रवार को हालात तब और बिगड़ गए जब दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और देखते ही देखते पत्थरबाजी शुरू हो गई. इस हिंसा में पुलिस भी अछूती नहीं रही— एसीपी सारनाथ का सिर फट गया, जबकि एक दरोगा समेत अन्य पुलिसकर्मी घायल हो गए.

यह विवाद आंबेडकर जयंती के दिन लगाए गए झंडे से शुरू हुआ, जिसे कथित रूप से फाड़कर जला दिया गया. इसके बाद विरोध प्रदर्शन, सड़क जाम और फिर दूसरे संगठन की एंट्री ने माहौल को और गरमा दिया. पुलिस ने पहले दिन स्थिति संभाल ली थी, लेकिन अगले ही दिन फिर हिंसा भड़क उठी.

घटना के बाद मौके पर पुलिस तैनात

पथराव में एसीपी सारनाथ विदुष सक्सेना गंभीर रूप से घायल हो गए—उनके सिर में चोट आई. एक दरोगा और एक अन्य पुलिसकर्मी भी जख्मी हो गए .घटना के बाद मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. पांच थानों की फोर्स के साथ वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित करने में जुट गए. डीसीपी वरुणा जोन, एसडीएम पिंडरा, तहसीलदार और अन्य प्रशासनिक अधिकारी लगातार हालात की निगरानी कर रहे हैं .फिलहाल क्षेत्र में तनाव बना हुआ है, लेकिन प्रशासन का दावा है कि स्थिति नियंत्रण में है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और दोषियों की पहचान कर कार्रवाई की तैयारी में जुटी है.

न्यूयॉर्क बर्बाद कर रहे हैं ममदानी : डोनाल्ड ट्रंप

न्यूयॉर्क. अमेरिका के सबसे बड़े शहर न्यू यार्क सिटी में टैक्स नीति को लेकर सियासी टकराव तेज हो गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और शहर के मेयर जेहरान ममदानी के बीच 'सेकेंड होम टैक्स' को लेकर खुली बहस छिड़ गई है। ममदानी ने शहर के राजस्व को बढ़ाने के लिए महंगे लग्जरी सेकेंड होम्स पर टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा है, जिसका ट्रंप ने कड़ा विरोध किया है.

तीसरी बार उप सभापति चुने गए हरिवंश

नई दिल्ली, 17 अप्रैल. राज्यसभा के मनोनीत सदस्य श्री हरिवंश को शुक्रवार को लगातार तीसरी बार उच्च सदन के उप सभापति के पद पर ध्वनिमत से चुन लिया गया ।नेता सदन जगत प्रकाश नड्डा ने श्री हरिवंश को उप सभापति चुने जाने का प्रस्ताव रखा जिसका भारतीय जनता पार्टी की सदस्य एस. फांगनोन कोन्याक ने समर्थन किया.

सदन ने इस प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित कर दिया। वह इस पद पर लगातार तीसरी बार चुने गये हैं. प्रस्ताव रखे जाने के दौरान विपक्ष के सदस्यों ने इस संबंध में कुछ कहना चाहा लेकिन सभापति ने उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी. विपक्ष की ओर से इस पद के लिए किसी का नामांकन नहीं

किया गया था ।यह पहला अवसर है जब किसी मनोनीत सदस्य को सदन का उप सभापति चुना गया है.

सभापति सी पी राधाकृष्णन ने जरूरी विधायी दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाने के बाद उप सभापति के चुनाव की प्रक्रिया शुरू करते हुए श्री नड्डा से अपना प्रस्ताव पेश करने को कहा. कुल पांच सदस्यों ने श्री हरिवंश के चुनाव के लिए प्रस्ताव पेश किये.

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और अन्य दलों के नेताओं ने सदन में

लगातार तीसरी बार उपसभापति चुने जाने पर श्री हरिवंश को बधाई दी. श्री मोदी ने कहा कि राज्य सभा के उपसभापति के रूप में लगातार तीसरी बार निर्वाचित होना, इस सदन का आपके प्रति गहरे विश्वास और बीते समय में सबको साथ लेकर चलने के आपके प्रयास पर एक तरह से सदन की मुहर है. श्री खरगे ने उम्मीद जताई कि उपसभापति विपक्ष के सदस्यों का विशेष ध्यान रखेंगे.

पंजाब में 'रेल रोको' आंदोलन पर ब्रेक, तीन दिन स्थगित

तीन दिन के लिए रोका रेल रोको आंदोलन

अभी टला आंदोलन, लेकिन सरकार पर दबाव बरकरार

चंडीगढ़, 17 अप्रैल. पंजाब में गेहूं खरीद को लेकर जारी किसान असंतोष के बीच प्रस्तावित 'रेल रोको' आंदोलन को फिलहाल तीन दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया है.

किसान यूनियनों ने यह फैसला रणनीतिक कारणों से लिया है, लेकिन सरकार के खिलाफ उनका गुस्सा कम नहीं हुआ है। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने साफ किया कि यह पीछे हटना नहीं, बल्कि आगे की लड़ाई की तैयारी है ।किसानों का आरोप है कि बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि से पहले ही फसल को नुकसान पहुंच चुका है, और अब सरकार की धीमी खरीद प्रक्रिया से उनकी परेशानियां और बढ़ गई हैं। मंडियों में गेहूं खराब हो रहा है और कीमतों में कटौती की जा रही है, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। हालांकि आंदोलन को अस्थायी रूप से रोका गया है.

अमानक बीज मामले में कार्रवाई : केन्द्रीय मंत्री

- किसान हितों के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति : शिवराज

नई दिल्ली, 17 अप्रैल. नई दिल्ली में मध्यप्रदेश के धार और खरगोन के किसानों ने केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलकर उनके सामने करेला की फसल में अमानक बीज और रोपे से हुए भारी नुकसान का मामला रखा.

जिस पर शिवराज सिंह ने इसे किसानों की आजीविका पर सीधा प्रहार मानते हुए तुरंत अधिकारियों को निर्देश दिए कि पीड़ित किसानों को उचित मुआवजा दिलाया जाए और दोषी कंपनी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए.

मध्यप्रदेश के धार और खरगोन के किसानों ने नई दिल्ली में उनसे भेंट कर करेला फसल में अमानक बीज और रोपे के कारण हुए गंभीर नुकसान की जानकारी दी. जिस पर चौहान ने तत्काल संबंधित अधिकारियों को साफ कहा कि प्रभावित किसानों को न्याय मिलना चाहिए और उन्हें उचित मुआवजा दिलाने की दिशा में तेजी से कार्रवाई होनी चाहिए साथ ही, उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि जिस कंपनी की भूमिका इस पूरे मामले में सामने आई है, उसके खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए.

सुको कांग्रेस नेता खेड़ा की जमानत अर्जी ठुकराई

नई दिल्ली. शीर्ष अदालत ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को बड़ा झटका देते हुए उनकी ट्रांजिट अग्रिम जमानत बढ़ाने की अर्जी ठुकरा दी है. यह मामला असम पुलिस द्वारा असम के मुख्यमंत्री सरमा की पत्नी की शिकायत पर दर्ज की गई एक प्राथमिकी से जुड़ा है। खेड़ा की उस अर्जी को भी अदालत ने ठुकरा दिया जिसमें उन्होंने ट्रांजिट जमानत को अगले मंगलवार तक बढ़ाने की मांग की थी ताकि वह सोमवार को असम की अदालत में पेश हो सकें. यह घटनाक्रम शीर्ष अदालत द्वारा उनकी अग्रिम जमानत पर रोक लगाने के दो दिन बाद सामने आया है.

राहुल पर एफआईआर का आदेश

- दोहरी नागरिकता के मामले में कानूनी पेच और गहरा गया
- लखनऊ पीठ ने जांच केंद्रीय एजेंसी से कराने को कहा है

लखनऊ, 17 अप्रैल. कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दोहरी नागरिकता के मामले में कानूनी पेच और गहरा गया है. इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश देते हुए जांच केंद्रीय एजेंसी से कराने को कहा है.

अदालत के इस फैसले के बाद अब पूरे मामले की जांच सीबीआई के हाथों में जाएगी ।यह मामला पहले निचली अदालत में खारिज हो चुका था, लेकिन याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि आरोपों की गंभीरता को देखते हुए विस्तृत जांच जरूरी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पहले एफआईआर दर्ज की जाए और फिर जांच प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए. इस फैसले के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है और आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सियासी घमासान बढ़ने की संभावना है.

राहुल मानहानि मामला : कोर्ट ने वादी पक्ष को चेताया

सुल्तानपुर. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से जुड़े मानहानि मामले में शुक्रवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने वादी पक्ष के लगातार स्थगन मांगने पर सख्त रुख अपनाते हुए भविष्य में किसी भी तरह की ढिलाई न बरतने की चेतावनी दी है. मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी .राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी शुक्ला ने बताया कि शुक्रवार को अदालत में धारा 311 दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के तहत दाखिल एक प्रार्थना पत्र पर बहस होनी थी.

परिसीमन बिल संसद में विफल : केजरीवाल

- परिसीमन विधेयक पर केंद्र सरकार घिरी
- केजरीवाल बोले- देश बदलाव चाहता है

नई दिल्ली, 17 अप्रैल. आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविन्द केजरीवाल ने परिसीमन विधेयक को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है.

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि संसद में इस विधेयक का विफल होना सरकार के अहंकार की हार है. केजरीवाल ने इसे राजनीतिक रूप से बड़ा संकेत बताते हुए दावा किया कि इससे

केंद्र की सरकार के खिलाफ माहौल बन रहा है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि यह केवल एक विधेयक की हार नहीं है, बल्कि यह जनता की भावना का प्रतिबिंब है. केजरीवाल ने यह भी दावा किया कि अब मोदी सरकार के पतन की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है.

विपक्ष के खिलाफ एजेंसियों का इस्तेमाल करने में व्यस्त

नई दिल्ली. आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविन्द केजरिवाल ने एक बार फिर केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों पर तीखा हमला बोला है. रुपये की लगातार गिरती कीमत, बढ़ती बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था की स्थिति को लेकर उन्होंने सरकार को कटघरे में खड़ा किया. केजरीवाल ने सवाल उठाया कि जब देश की अर्थव्यवस्था वैश्विक स्तर पर नीचे खिसक रही है और आम आदमी की रोजी-रोटी संकट में है, तब सरकार विपक्षी नेताओं के खिलाफ एजेंसियों का इस्तेमाल करने में व्यस्त क्यों है.

आज का इतिहास

1612- मुगल बादशाह शाहजहां ने मुमताज से निकाह किया.

1621- सिक्खों के नौवें गुरु गुरु तेग बहादुर का जन्म.

1859- वर्ष 1857 विद्रोह के नेता तात्यां तोपे को फांसी दी गयी.

1902-अपराधियों की पहचान के लिए डेनमार्क ने सबसे पहले फिंगरप्रिंट दर्ज करने शुरू किए.

1906- सैन फ्रांसिस्को में भूकंप और आग से लगभग 4000 लोगों की मौत.

1917- महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के लिए बिहार के चंपारण का चयन कियाय.

आस्था स्थिर नहीं होते, बल्कि समय के साथ बदलते रहते

तिरूअंतरमपुरम. मकेरल के सबरीमाला टेम्पल में महिलाओं के प्रवेश को लेकर चल रहा विवाद एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में चर्चा के केंद्र में है। पांचवें दिन की सुनवाई में याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने अहम दलील देते हुए कहा कि आस्था और विश्वास समय के साथ बदलते रहते हैं और इन्हें कानून के जरिए तय नहीं किया जा सकता ।यह मामला 2018 के उस ऐतिहासिक फैसले से जुड़ा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर लगी रोक हटा दी थी। इस फैसले के खिलाफ दाखिल पुनर्विचार याचिकाओं पर अब विस्तृत सुनवाई जारी है.

बंगाल चुनाव : मंजूरी प्राप्त वोटरों के नाम सूची में जोड़े जाएंगे

19 न्यायाधीशों द्वारा आवेदनों की होगी जांच

21 तक मिलेगी मंजूरी उन्हीं नामों को शामिल किया जाएगा

कोलकाता, 17 अप्रैल. पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) मनोज अग्रवाल ने कहा है कि उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार अधिकरण से मंजूरी प्राप्त मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल किए जाएंगे.

पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव

अग्रवाल ने गुरुवार रात मीडिया को बताया कि अधिकरण में 19 न्यायाधीशों द्वारा आवेदनों की जांच की जाएगी और तदनुसार उनका निपटान किया जाएगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन लोगों के नाम हटा दिए गए थे, अधिकरण से मंजूरी मिलने के बाद उन्हें फिर से मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा.

मुख्य चुनाव अधिकारी ने कहा कि मतदाता सूची को नौ अप्रैल तक प्रकाशित किया जा चुका है। जिन नामों को 21 अप्रैल तक मंजूरी मिल जाएगी, उन्हें सूची में शामिल कर लिया जाएगा और उन मतदाताओं को उनका मतदान का अधिकार वापस मिल जाएगा। मामलों के निपटान की संख्या पर उन्होंने कहा कि अभी तक डैशबोर्ड नहीं बना है, इसलिए सटीक आंकड़ा देना संभव नहीं है.

अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि प्रभावित हुए 27 लाख से अधिक मतदाताओं में से कितनों को अब तक मंजूरी मिली है.

अंतिम समय में नाम जोड़ने की चिंताओं पर उन्होंने कहा कि आयोग एक सॉफ्टवेयर सिस्टम पर काम कर रहा है ताकि मंजूरी मिलने के बाद नामों को आसानी से जोड़ा जा सके.

हालांकि, जमीनी स्तर पर काम कर रहे चुनाव अधिकारियों ने इतनी कम समयसीमा में इस निर्देश को लागू करने की व्यवहारिकता पर गंभीर चिंता व्यक्त की है. 23 अप्रैल को होने वाले मतदान की तैयारी में जुटे एक अधिकारी ने बताया कि मतदान से दो दिन पहले तक नए नाम जोड़ने पड़ सकते हैं.

कोलकाता में मर्लिन ग्रुप पर ईडी ने छापा मारा

कोलकाता. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार तड़के कोलकाता स्थित रियल एस्टेट डेवलपर मर्लिन ग्रुप की कई जगहों पर समन्वित छापेमारी की. माना जा रहा है कि ईडी की यह कार्रवाई, कंपनी की कुछ कथित वित्तीय अनियमितताओं की चल रही जांच का हिस्सा है। आशंका है कि कंपनी ने धन शोधन कानूनों का उल्लंघन किया है. अधिकारियों के अनुसार, ईडी की टीमें शहर और आसपास के इलाकों में कई स्थानों पर तैनात की गईं. जिन ठिकानों पर तलाशी ली गई, उनमें मिडलटन स्ट्रीट और साल्ट लेक के सीएफ ब्लॉक स्थित मर्लिन ग्रुप की संपत्तियां शामिल हैं. जांच एजेंसी ने डीसी पाल ग्रुप के एक कार्यालय में भी तलाशी अभियान चलाया, जिससे संकेत मिलता है कि जांच अब संबंधित संस्थाओं और कारोबारी संबंधों तक भी फैल सकती है. अधिकारियों ने अभी तक कोई विस्तृत आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है तलाशी से जुड़े ईडी अधिकारियों का कहना है कि मामला भूमि सौदों और स्वामित्व रिकॉर्ड से जुड़े गंभीर आरोपों से संबंधित है. मर्लिन ग्रुप के प्रमोटरों और कंपनी

पर आरोप है कि उन्होंने फर्जी दस्तावेजों का उपयोग कर स्वामित्व की झूठी कड़ी तैयार की और भूमि हड़प ली. ईडी का यह भी आरोप है कि आरोपियों ने कथित रूप से कब्जाई गई जमीन का व्यावसायिक शोषण करते हुए बड़े पैमाने पर रियल एस्टेट परियोजनाएं शुरू कीं. एजेंसी के अनुसार, फर्जी दस्तावेजों के जरिए खुद को वैध मालिक दिखाकर आरोपियों ने आम जनता को इन परियोजनाओं में बड़ी रकम निवेश करने के लिए प्रेरित किया ।फिलहाल यह अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है कि इस कार्रवाई के दौरान कोई जब्ती या गिरफ्तारी हुई है या नहीं. एक अन्य अधिकारी ने बताया कि जांचकर्ता दस्तावेजों, डिजिटल रिकॉर्ड और वित्तीय लेन-देन की जांच कर रहे हैं, जिसके कारण छापेमारी अगले कुछ दिनों तक जारी रह सकती है। मर्लिन ग्रुप और डीसी पाल ग्रुप के प्रतिनिधियों ने अब तक इस मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है.

बालेन सरकार का बड़ा एक्शन

- पूर्व पीएम, 3 राष्ट्रपति और पूर्व राजा तक जांच का दायरा
- 2006 से अब तक के नेताओं की संपत्ति जांच शुरू

काठमांडू, 17 अप्रैल. नेपाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ अब तक की सबसे व्यापक और सख्त कार्रवाई शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री बालेन शाह के नेतृत्व में नई सरकार ने 2006 के बाद से सार्वजनिक पदों पर रहे शीर्ष नेताओं और अधिकारियों की संपत्तियों की जांच के आदेश दिए हैं.

इस बड़े कदम के तहत पूर्व प्रधानमंत्रियों, राष्ट्रपतियों, यहां तक कि पूर्व राजशाही से जुड़े लोगों को भी जांच के दायरे में लाया गया है ।सरकार ने इसके लिए एक पांच सदस्यीय न्यायिक पैनल का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट जज राजेंद्र कुमार भंडारी कर रहे हैं। इस जांच का मुख्य उद्देश्य अवैध संपत्ति, बेनामी निवेश और शेल कंपनियों के जरिए अर्जित धन का पता लगाना है। यह कार्रवाई 2025 में हुए बड़े युवा आंदोलन के बाद आई है, जिसने नेपाल की राजनीति में बड़ा बदलाव ला दिया। अब इस जांच को देश में पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में एक निर्णायक कदम माना जा रहा है ।इस जांच के दायरे में देश के 7 पूर्व प्रधानमंत्री, 3 पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व राजा, सैकड़ों मंत्री और वरिष्ठ नौकरशाह शामिल हैं ।इस बड़े कदम की पृष्ठभूमि में 2025 में हुआ व्यापक 'जेन-जी युवा आंदोलन है, जिसने भ्रष्टाचार के खिलाफ देशव्यापी माहौल बनाया.

ट्रंप ने उपराज्यपाल बनने पर तरनजीत संधू को दी बधाई

तरनजीत सिंह संधू, जो दिल्ली के 21वें उपराज्यपाल

2020 से 2024 तक अमेरिका में भारत के 28वें राजदूत

नई दिल्ली, 17 अप्रैल. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को दिल्ली के उपराज्यपाल का पदभार संभालने पर तरनजीत संधू को बधाई दी.

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा कि दिल्ली के नए उपराज्यपाल बनने पर तरनजीत संधू को बधाई.उन्होंने कहा कि एक अनुभवी राजनयिक और अमेरिका में पूर्व राजदूत के रूप में तरनजीत संधू ने हमेशा अमेरिका-भारत संबंधों को मजबूत करने के लिए गहरी प्रतिबद्धता दिखाई है. ट्रंप ने कहा कि दिल्ली की प्रगति का नेतृत्व करने और वैश्विक संबंधों को आगे बढ़ाने में उनकी सफलता की कामना करता हूं.तरनजीत सिंह संधू, जो दिल्ली के 21वें उपराज्यपाल के रूप में कार्यरत हैं, फरवरी 2020 से जनवरी 2024 तक अमेरिका में भारत के 28वें राजदूत रहे.

अभियान सम्राट चौधरी ने भारत की जनगणना 2027 का बिहार में किया शुभारंभ

जनगणना बिहार के उज्ज्वल भविष्य की दिशा में मजबूत

पटना,17 अप्रैल.बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शुक्रवार को विश्व के सबसे बड़े प्रशासनिक एवं सांख्यिकीय अभियान- भारत की जनगणना-2027 का राज्य में शुभारंभ किया.

चौधरी ने भारत की जनगणना-2027 का सचिवालय से माउस क्लिक कर शुभारंभ किया.इस अवसर पर श्री चौधरी ने राज्यवासियों से जनगणना प्रक्रिया में सक्रिय एवं उत्साहपूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया है.मुख्यमंत्री श्री चौधरी ने कहा कि जनगणना सुशासन की आधारशिला है, जो आगामी वर्षों में विकास

योजनाओं, नीतियों और कल्याणकारी कार्यक्रमों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगी.उन्होंने कहा कि जनगणना-2027 तकनीकी दृष्टि से एक ऐतिहासिक पहल है.इसमें पहली बार पूर्णत: डिजिटल डेटा संग्रहण तथा स्व-गणना की सुविधा 17 अप्रैल 2026 से 01 मई 2026 उपलब्ध रहेगी.उन्होंने कहा कि राज्य में जनगणना-2027 के प्रथम चरण में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य 02 मई 2026 से 31 मई 2026 तक किया जाएगा. मुख्यमंत्री चौधरी ने राज्य के सभी नागरिकों से अपील करते हुये कहा कि वे इस राष्ट्रीय महत्व के अभियान में बढ़-चढ़कर भाग लें.स्व-गणना के माध्यम से या प्रगणकों को सहयोग प्रदान कर एक सटीक, समावेशी और विश्वसनीय जनगणना संपन्न करने में अपना सहयोग दें. जनगणना-2027 बिहार एवं देश के उज्ज्वल भविष्य की दिशा में एक मजबूत आधार तैयार करेगी.

आरक्षण पारित होने पर क्रांतिकारी दिन बन जायेगा : सम्राट

पटना. बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शुक्रवार को कहा कि महिला आरक्षण बिल यदि आज लोकसभा से पारित होता है तो 17 अप्रैल का दिन देश की महिलाओं के लिए क्रांतिकारी दिन बन जायेगा .मुख्यमंत्री श्री चौधरी आज नारी शक्ति वंदन अभियान के तहत आयोजित नारी शक्ति फॉर विकसित भारत रन कार्यक्रम में शामिल हुए .श्री चौधरी ने जे.पी. गंगा पथ स्थित दीघा गोलंबर पर आयोजित इस कार्यक्रम में शामिल महिलाओं को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.

आयकर विभाग ने तृणमूल विधायक के ठिकानों पर की छापेमारी

कोलकाता. आयकर विभाग ने शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस के रासबिहारी निर्वाचन क्षेत्र से निवर्तमान विधायक देवाशीष कुमार के आवास पर छापेमारी की, जिससे विधानसभा चुनाव से पहले इलाके में राजनीतिक तनाव पैदा हो गया है .सूत्रों ने बताया कि अधिकारियों ने दक्षिण कोलकाता के मनोहरपुकुर रोड स्थित श्री कुमार के आवास पर सुबह तलाशी शुरू की .जब छापेमारी शुरू हुई उस समय तृणमूल उम्मीदवार घर पर ही मौजूद थे .इसके साथ ही पास में स्थित उनके चुनाव कार्यालय और मोतीलाल नेहरू रोड स्थित एक पार्टी कार्यालय में भी तलाशी ली जा रही है .तीनों स्थानों के बाहर केंद्रीय बलों को तैनात किया गया है और आयकर अधिकारी तलाशी ले रहे हैं .छापेमारी के पीछे के सटीक कारण का तुरंत पता नहीं चल पाया है .यह घटनाक्रम प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा तृणमूल नेता की चल रही जांच के बीच आया है .श्री कुमार को जमीन हड़पने के मामले में कई बार समन भेजा गया था और एक, तीन और नौ अप्रैल को साल्ट लेक के सीजीओ कॉम्प्लेक्स में उनसे पूछताछ की गई थी .ईडी के सामने पेश होने के बाद श्री कुमार ने विस्तृत टिप्पणी करने से परहेज किया था और कहा था कि उनकी पार्टी इसका जवाब देगी. मोतीलाल नेहरू रोड पर पार्टी कार्यालय के बाहर तृणमूल कार्यकर्ताओं और समर्थकों के इकट्ठा होने और विरोध प्रदर्शन करने से राजनीतिक तनाव बढ़ गया.

राहुल गांधी आज तमिलनाडु में चुनावी सभा को करेंगे संबोधित

नई दिल्ली. लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी शनिवार को तमिलनाडु के विधानसभा चुनावी दौरे पर रहेंगे. इस दौरान वह राज्य में तीन बड़ी जनसभाओं को संबोधित करेंगे और पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। राहुल गांधी के इस दौरे को आगामी चुनावों के मद्देनज़र अहम माना जा रहा है, जहां वह विभिन्न क्षेत्रों में जनता से सीधा संवाद करेंगे। राहुल गांधी का कार्यक्रम शनिवार सुबह 11-30 बजे शुरू होगा। वह सबसे पहले पोननेरी में जनसभा करेंगे उसके बाद दोपहर एक बजे रानीपेट ज़िले के शोलिंगर सर्कल दूसरी जनसभा को संबोधित करेंगे। श्री गांधी दोपहर 3-30 बजे तिरुचिरापल्ली क्षेत्र के थुरैयूर में तीसरी जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस पार्टी के मुताबिक, इन जनसभाओं के जरिए श्री राहुल गांधी राज्य के मतदाताओं से सीधे संवाद करेंगे और स्थानीय मुद्दों पर अपनी बात रखेंगे.